क्षेत्रीय समाचार एकांश

देहरादून (उत्तराखण्ड)

बुधवार 02.07.2025 समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये की रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।
- कांवड़ यात्रा के दौरान राज्य में यात्रा मार्ग के सभी खाद्य विक्रेताओं के लिए फूड लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य।
- प्रदेश में अब तक 58 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित करने के साथ ही 11 लाख से अधिक मरीजों को कैशलेस उपचार दिया गया।
- साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता बढ़ाने के उद्देश्य से आईआईटी रुड़की में विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमण्डल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये की रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत अगले दो वर्षों में साढे तीन करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन किया जाएगा, जिनमें से 1 करोड़ बयानब्बे लाख लाभार्थी पहली बार कार्यबल से जुड़ेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली योजना एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक सृजित नौकरियों पर लागू होगी।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश में खेलों की स्थिति को बेहतर बनाना और लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस नीति के तहत भारत ने शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है।

इसके अलावा कैबिनेट ने अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को भी स्वीकृति दी है, जिसके लिए एक लाख करोड़ रुपये का कोष रखा गया है। यह योजना निजी क्षेत्र की फंडिंग से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए बनाई गई है और इसका उद्देश्य उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना, तकनीक को अपनाना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की गवर्निंग बोर्ड इस योजना को रणनीतिक दिशा प्रदान करेगी।

कांवड़ यात्रा–खाद्य सुरक्षा

प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा के सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब सभी खाद्य विक्रेताओं को अपने फूड लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र को दुकान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वालों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बाइट– वॉयस कास्ट, सेकेण्ड

स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देशन में श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है। होटल, ढाबों, ठेलियों और रेस्टोरेंट्स को 'फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड' प्रमुखता से लगाना होगा ताकि ग्राहकों को भोजन की गुणवत्ता की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में तैनात विशेष टीमें यात्रा मार्ग के भंडारों और पंडालों से दूध, मिठाई, तेल और मसालों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज रही हैं। मानक पर खरे न उतरने वाले प्रतिष्ठानों को तत्काल बंद किया जाएगा। सरकार ने जनता को जागरूक करने के लिए प्रचार अभियान शुरू किया है और टोल फ्री नंबर 1 8 0 0 1 8 0 4 2 4 6 पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी दी है। हर जिले से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है और लापरवाही पर अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने धार्मिक संस्थाओं और भंडारा संचालकों से अपील की है कि श्रद्धालुओं को केवल शुद्ध और सुरक्षित भोजन ही परोसा जाए ताकि इस आस्था के पर्व में स्वास्थ्य का संकल्प भी पूरा हो सके।

राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस

राज्य सरकार, जनता को न्यूनतम दर पर स्वास्थ्य सुविधांए देने और स्वस्थ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिये पूरी प्रतिबद्धता के काम कर रही है। प्रदेश में अब तक 58 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 11 लाख से अधिक मरीजों को दो हजार एक सौ करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार का लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार का लक्ष्य राज्य के हर नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना है।

बाइट– वॉयस कास्ट, सेकेण्ड

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर कल मुख्यमंत्री आवास में प्रदेशभर से आए चिकित्सकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक, केवल एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से पांच पहले ही संचालित हो चुके हैं और दो अन्य का निर्माण कार्य प्रगति पर है। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और यूरोलॉजी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हल्द्वानी में राज्य का पहला आधुनिक कैंसर संस्थान भी निर्माणाधीन है। राज्य में प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है जो आपात स्थिति में सुदूर क्षेत्रों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। इसके अलावा 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की सुविधा मरीजों को निःशुल्क दी जा रही है। श्री धामी ने यह भी बताया कि सरकार टेलीमेडिसिन सेवाओं के जरिए दूरदराज के गांवों तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह उपलब्ध करा रही है।

जागरूकता कार्यक्रम

साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को देखते हुए आईआईटी रुड़की में विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डेटा लीक, पासवर्ड सुरक्षा और सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक (अपराध) हरिद्वार जितेंद्र मेहरा ने कहा कि डिजिटल युग में सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी नई तरकीबों से युवाओं को निशाना बना रहे हैं, इसलिए हर नागरिक का जागरूक होना जरूरी है।

घंटाघर सौंदर्यीकरण

राजधानी देहरादून का ऐतिहासिक घंटाघर अब अपने नए और भव्य स्वरूप में नजर आने लगा है। जिलाधिकारी सविन बंसल की निगरानी में घंटाघर के सौंदर्यीकरण का कार्य तेज़ी से पूरा किया गया है। प्रशासन का दावा है कि इस परिवर्तन से घंटाघर न केवल आकर्षक बना है, बल्कि यातायात संचालन भी बेहतर हुआ है।

गौरतलब है कि जिलाधिकारी ने देहरादून में तैनाती के शुरुआती महीनों में ही घंटाघर और अन्य चौक–चौराहों के सौंदर्यीकरण का डिज़ाइन, सर्वे और कार्ययोजना तैयार कर ली थी। इसके बाद बजट प्रबंधन करते हुए स्मार्ट सिटी योजना की धनराशि से काम शुरू करवाए गए। घंटाघर को पारंपरिक लोक शैली में सजाया गया है, जिससे न केवल स्थानीय लोगों को सुविधा होगी, बल्कि पर्यटक भी उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा की झलक यहां देख सकेंगे।

प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में शहर के कई प्रमुख स्थलों पर सौंदर्यीकरण और यातायात सुगमता से जुड़े निर्माण कार्य जारी हैं। इन कार्यों की सतत निगरानी स्वयं जिलाधिकारी कर रहे हैं।

पुरस्कार

नई दिल्ली में हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के सम्मेलन में देहरादून के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडेय को देश के सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट अधिकारी का पुरस्कार मिला। यह सम्मान उन्हें उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और दूरदराज क्षेत्रों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंचाने के लिए दिया गया। उन्होंने मोबाइल वैन शिविरों के माध्यम से पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराईं। उनके प्रयासों से देहरादून कार्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। यह पुरस्कार उन्हें 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने प्रदान किया।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

केंद्रीय मंत्रिमंडल की करीब एक लाख करोड़ रूपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

इस खबर पर हिन्दुस्तान लिखता है– पहली बार प्राइवेट नौकरी पर केंद्र अतरिक्त वेतन देगा।

अमर उजाल ने अपने शीर्षक में लिखा है– दो साल में युवाओं को मिलेगी 3.5 करोड़ नौकरियां, खर्च होंगे 99.44 हजार करोड़।

राष्ट्रीय सहारा लिखता है– रोजगार प्रोत्साहन के लिए एक लाख करोड़।

नवोदय टाइम्स ने शीर्षक दिया है– पहली नौकरी पर रूपये 15000।

महेंद्र भटट के लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है।

राष्ट्रीय सहारा लिखता लिखता है– महेंद्र भटृट को फिर भाजपा की कमान।